An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani Advocate Bombay High Court. Specialist in Multi Media Law and Regulation/ Corporate Law and Regulation and Taxation.



# मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक सामयिक स्तंभ

लेग्डकः अशोक मनसुग्डानी एडवोकेट वॉम्बे हाई कोर्ट मल्टी मीडिया कानून और रेग्यूलेशन/कॉरपोरेट कानून और रेग्यूलेशन और टैक्सेशन के विशेषन्न।

# INDIA MOVES TO A DIGITAL ERA

Latest FICCI survey shows a distinctive move of Indian media to a Digital Era

# A. FICCI FRAMES PUNTS FOR A DIGITAL FUTURE

- ◆ Every summer, the **Federation of Chambers of Commerce and Industry (FICCI)** holds an annual media conference in Mumbai. Among its key
  - highlights is a definitive report prepared by **Ernest and Young (EY)** with the assistance of industry leaders and media experts. It is unparalleled in its depth and credibility.



- This year's Report released in early May
   2023 has punted that the future of the Indian Media and Entertainment Industry will be digital.
- ◆ The principal author of the Report, Mr Ashish Pherwani, Partner EY, states in the Report that "The Indian M&E consumer base is large but heterogenous, hungry for content but willing to pay only for value, and more than ready to experiment with technology, be it streaming, digital payments, online education, virtual experiences, e-commerce, social media, or gaming."
- ◆ The head of the **Jio Media and Content** business of **Reliance**, **Ms Jyoti Deshpande**, said, "It is an exciting time to be in the M&E business, as we leverage the three pillars of the industry content,

# डिजिटल युग की ओर अग्रसर है भारत

नवीनतम फिक्की सर्वेक्षण भारतीय मीडिया के डिजिटल युग की ओर एक विशिष्ट कदम दर्शाता है।

- ए. फिक्की फ्रेम्स डिजिटल भविष्य की वकालत करता है
  - हर गर्मियों में, फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) मुंबई में एक वार्षिक मीडिया सम्मेलन का



आयोजन करता है। इसकी मुख विशेषताओं में अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) द्धारा उद्योग जगत के नेताओं और मीडिया विशेषज्ञों की सहायता से तैयार की गयी एक निश्चित रिपोर्ट है। यह अपनी गहराई और विश्वनीयता में अद्वितीय है।

मई 2023 की शुरूआत में
 जारी इस साल की रिपोर्ट में कहा

गया है कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का भविष्य डिजिटल होगा।

- ♦ रिपोर्ट में प्रमुख लेखक श्री आशीष फेरवानी, पार्टनर ईवाई, ने रिपोर्ट में कहा है कि 'भारतीय एम एंड ई उपभोक्ता आधार वड़ा लेकिन विविध है, सामग्री के लिए भूखा है, लेकिन केवल मूल्यों के लिए भुगतान करने को तैयार है और प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार है, चाहे वह स्ट्रीमिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, आभासी अनुभव, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया या गेमिंग हो।'
- ◆ रिलायंस के जियो मीडिया और कंटेंट बिजनेस के प्रमुख सुश्री ज्योति देशपांडे ने कहा 'यह एम एंड ई विजनेस में रहने का एक रोमांचक समय है. क्योंकि हम तकनीकी नवाचार द्वारा संचालित

commerce, and community, fuelled by technological innovation."

#### KEY HIGHLIGHTS OF THE REPORT

- ◆ The Indian Media and Entertainment (M&E) Sector grew by 20% in 2022 to reach INR 2.1 trillion (US\$ 26.2 billion), 10% above its prepandemic levels in 2019.
- ◆ It is expected to grow to a further INR 734 billion to reach INR 2.83 trillion in 2025.
- ◆ Digital media grew by INR 132 billion from 16% in 2019 to 27% in 2022 to reach INR 571 billion and 48% of all advertising revenues.
- ◆ Paid video subscriptions reached 99 million in 2022, across almost 45 million households in India, with a total viewership of around 135 to 180 million users.
- ◆ The digital segment is expected to grow to INR 862 billion by 2025 at a 15% CAGR.

#### TV UNI VERSE

◆ Television advertising grew 2% at the end of

**2022**, just behind its 2019 levels, on the back of volume growth.

◆ TV Subscription revenue continued to fall for the third year in a row, experiencing a 4% degrowth due to a reduction of five million pay-TV homes and stagnant consumer-end ARPUs.



- ◆ The fall in **pay television homes** has been attributed to both **cord-cutting at** the top end and *movement* to **Free Television (DD FreeDish)** at the bottom of the customer pyramid.
- ◆ There were 120 million active Pay TV homes and 45 million Free TV homes in 2022.
- ♦ Smart TV sets, however, increased to 25 million though only 8 to 10 million connected to the Internet daily.

#### **FUTURE OUTLOOK FOR TV -2025**

◆ Total television screens (*linear and bi-directional*) are expected to reach 206 million by 2025 from 180 million today.

उद्योग के तीन स्तंभों - कंटेंट, वाणिज्य और समुदाय का लाभ उठाते हैं।

### रिपोर्ट की मुख्य बातें

- ♦ भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग (एमएंडई) क्षेत्र 2022 में 20% बढ़कर 2.1 ट्रिलियन रूपये (26.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया, जो 2019 में अपने महामरी पूर्वस्तर से 10% अधिक है।
- ◆ 2025 में इसके 734 अरब रूपये बढ़कर 2.83 ट्रिलियन रूपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
- ♦ डिजिटल मीडिया 2019 में 16% से 132 बिलियन रूपये बढ़कर 2022 में 27% बढ़कर 571 बिलियन रूपये और सभी विज्ञापन राजस्व का 48% हो गया।
- ◆ 2022 में भारत के लगभग 45 मिलियन घरों में पेड वीडियो सब्सकीप्शन 99 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें कुल दर्शकों की संख्या लगभग 135 से 180 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक थी।
- ◆ डिजिटल सेगमेंट के 15% सीएजीआर पर 2025 तक 862 मिलियन रूपये तक बढ़ने की उम्मीद है।

#### टीवी जगत

- मात्रा वृद्धि के कारण, 2022
   के अंत में टेलीविजन विज्ञापन में
   2% की वृद्धि हुई, जो कि 2019 के
   स्तर से ठीक पीछे है।
- ◆ टीवी सब्सकीप्शन राजस्व में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट जारी रही, पांच मीलियन पे टीवी घरों की कमी और स्थिर उपभोक्ता अंत में स्थिर एआरपीयू के कारण ४% की डी-गोथ देखी गयी।
- पे टेलीविजन घरों में गिरावट के लिए सबसे प्रमुख योगदान कार्ड किटिंग और ग्राहक पिरामिड के निचले भाग में फ्री टेलीविजन (डीडी फ्रीडिश) की ओर बढ़ना दोनों है।
- ◆ 2022 में 120 मिलियन सिक्रिय टीवी घर और 45 मिलियन फ्री टीवी घर थे।
- ♦ हालांकि स्मार्ट टीवी सेट बढ़कर 25 मिलियन हो गये, हालांकि प्रतिदिन केवल 8 से 10 मिलियन ही इंटरनेट से जुड़ते हैं।

### टीवी के लिए भविष्य का दृष्टिकोण-2025

कुल टेलीविजन स्क्रीन (लीनियर व बॉय डायरेक्शनल) आज के 180 मिलियन से बढ़कर 2025 तक 206 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

- ♦ However, the EY Report forecasts that by 2025 the mix will be different. The growth of overall television households would be driven by connected TVs which could cross 40 million by 2025, and Free Television (Free Dish) could cross 50 million.
- ◆ Pay TV households are expected to decline by two million in 2023 before falling slowly to 116 million homes by 2025.
- ◆ Total television segment revenues are expected to grow at a CAGR of 4% to reach INR 796 billion by 2025.
- ◆ The **Report** forecasts that **LCOs** will **rejuvenate** their last-mile distribution businesses with digital offerings and drive connectivity for India, supported by larger telcos and ISPs.

#### COMMENT

- ◆ The two forecasts are starkly different. Total TV segment revenues are expected to grow at a CAGR of only 4 per cent. In contrast, Digital Media revenues are expected to grow at a CAGR of 15% by 2025.
- ◆ This is a wake-up call not just for the TV distribution industry but also for the linear broadcast TV industry.
- ◆ In the Report, one of the astute observers of the M/E Industry, Mr Gurjeev Singh Kapoor of Disney Star, says that "TV has an unparalleled reach of 900 million viewers. With less than 70 per cent of homes having a TV in India, the market remains under-penetrated, offering significant potential for growth in the years ahead."
- ♦ BARC has not officially released active TV home data for three years. The last Indian Census took place in 1991.
- ◆ It is difficult to determine the exact number of homes in India, but it is estimated to be around 300 million.
- ◆ The TV distribution industry must embrace broadband technology and partner with telecom companies to ensure its survival if the Multi System Operators do not rise to meet the challenge.
- ◆ The future of Indian TV distribution is clearly in the rural areas with many Cable TV dark areas.

- ♦ हालांकि, ईवाई रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक मिश्रण कुछ अलग होगा।समग्र टेलीविजन घरों की वृद्धि कनेक्टेड टीवी द्वारा संचालित होगी जो 2025 तक 40 मिलियन घरों को पार कर सकती है और फ्री टेलीविजन (फ्री डिश) 50 मिलियन को पार कर सकती है।
- ◆ 2025 तक धीरे-धीरे घटकर 116 मिलियन घरों तक पहुंचने से पहले 2023 में पे टीवी घरों में 20 लाख की गिरावट आने की उम्मीद है।
- 2025 तक कुल टेलीविजन खंड का राजस्व 4% की सीएजीआर से बढ़कर 796 विलियन रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि एलसीओ बड़ी दूरसंचार कंपनियों और आईएसपी द्वारा समर्थित डिजिटल पेशकशों और भारत के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर अपने अंतिम मील वितरण व्यवसायों को फिर से जीवंत करेगा।

#### टिप्पणी

- दोनों पूर्वानुमान विल्कुल अलग है। कुल टीवी सेगमेंट का राजस्व केवल 4 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। इसके विपरीत, डिजिटल मीडिया राजस्व 2025 तक 15% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।
- यह न केवल टीवी वितरण उद्योग के लिए बल्कि लीनियर प्रसारण टीवी उद्योग के लिए भी एक चेतावनी है।
- ♦ रिपोर्ट में, एम/ई उद्योग के चतुर पर्यवेक्षकों में से एक, डिज्जी स्टार के श्री गुरजीव सिंह कपूर का कहना है कि 'टीवी की 900 मिलियन दर्शकों तक अद्वितीय पहुंच है। भारत में 70 प्रतिशत से भी कम घरों में टीवी होने के कारण वाजार की पहुंच अभी भी कम है, जो आने वाले वर्षों में विकास की महत्वपूर्ण संभावनायें पेश करता है।
- बीएआरसी ने आधिकारिक तौर पर तीन वर्षों से सक्रिय टीवी होम डेटा जारी नहीं किया है | आखिरी भारतीय जनगणना 1991 में हुई थी |
- भारत के घरों की सटीक संख्या निर्धारित करना कठिन है, लेकिन अनुमान है कि यह लगभग 300 मिलियन है।
- यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर चुनौती का सामना करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो टीवी वितरण उद्योग को अपना आस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए ब्रॉडवैंड तकनीकी को अपनाना चाहिए और दूरसंचार कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए /
- भारतीय टीवी वितरण का भविष्य स्पष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में है
   जहां कई केवल टीवी अंधेरे क्षेत्र हैं।एक अन्य अवसर 45

- Another opportunity is to persuade 45 million Free Dish homes to convert to low-cost but friendly pay TV packages.
- ◆ All is not over for the vibrant TV distribution industry, but this is not the time for complacency. But this writer feels that retrieving the eroding subscriber base by 2025 would be too late.

# B. ONLINE GAMING IS A ROARING SUCCESS IN INDIA

- ◆ Online gaming is one of the fastest-growing segments of the Indian M/E sector in India, with runaway potential in the balance decade. It is the *fourth-largest* segment of the Indian M&E sector.
- ◆ The online gaming segment grew 35% in 2022 to reach INR 135 billion.
- ◆ The FICCI Frames EY Report 2023 and All India Gaming Federation estimate that online gamers grew to 421 million in 2022. Around 90 to 100 million are frequent players of games. Transaction-based game revenues

grew 39%, while casual gaming grew 20%.

- ◆ The **Report** further reveals that:
  - Transaction-based game revenues crossed INR 100 billion.
  - The resumption of sporting events, including marquee events like FIFA, Asia Cup, IPL, and T20 World Cup, drove fantasy sports growth.
  - Close to 25% of online gamers are paid gamers, increasing by approximately 2 million per month.

#### **TOUGH REGULATORY MEASURES**

- ♦ A Press Information Bureau release on April 20, 2024, noted that:
  - The online gaming industry in India has seen immense growth recently. However, various social and economic concerns have emerged from this industry.
  - The Ministry of Electronics and IT (MeitY) introduced various checks and balances through relevant amendments to IT Rules 2021, notified on April 06, 2023.

- मिलियन फ्री डिश घरों को कम लागत वाले लेकिन अनुकूल पे टीवी पैकेज में वदलने के लिए राजी करना है।
- जीवंत टीवी वितरण उद्योग के लिए सब कुछ खम नहीं हुआ है, लेकिन यह आत्मसंतुष्टि का समय नहीं है | लेकिन इस लेखक को लगता है कि 2025 तक घटते ग्राहक आधार को पुनःप्राप्त करने में बहुत देर हो जायेगी |

### बी. भारत में जबरदस्त सफल रहा है ऑनलाइन गेमिंग

- ऑन लाइन गेमिंग भारत में भारतीय एम/ई क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जिसमें शेष दशक में तेजी से बढ़ने की संभावना है। यह भारतीय एमएंडई क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा खंड है।
- ◆ ऑनलाइन गेमिंग खंड 2022 में 35% बढ़कर 135 बिलियन रूपये तक पहुंच गया है।
  - ◆ फिक्की फ्रेम्स ईवाई रिपोर्ट 2023 और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का अनुमान है कि 2022 में ऑनलाइन गेमर्स बढ़कर 421 मिलियन हो गये हैं | लगभग 90 से 100 मिलियन लोग गेम के लगातार खिलाड़ी हैं | लेन-देन आधारित गेम राजस्व में 39% की वृद्धि हुई है,

जबिक **कैजुअल गेमिंग** में 20% की वृद्धि हुई है।

- ◆ रिपोर्ट आगे बताती है
  - लेन-देन आधारित गेम राजस्व 100 बिलियन रूपये पार कर गया है।
  - फीफा, एशिया कप, आईपीएल और टी20 विश्व कप जैसे प्रमुख आयोजनों सिहत खेल आयोजनों की बहाली ने फैंटेसी खेलों के विकास को बढ़ावा दिया।
  - लगभग 25% ऑनलाइन गेमर्स पेड गेमर्स हैं, जो प्रति
     माह लगभग 2 मिलियन की वृद्धि कर रहे हैं।

#### सख्त नियामक उपाय

- ◆ 20 अप्रैल 2023 को प्रेस सूचना ब्यूरो की एक विज्ञिप्त में कहा गया है कि
  - भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हालही में भारी वृद्धि देखी गयी हैं । हालांकि इस उद्योग से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चिंतायें उभरी हैं ।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 6 अप्रैल 2023 को अधिसूचित आईटी नियम 2021 में प्रासंगिक संशोधनों के माध्यम से विभिन्न जांच और संतुलन पेश किये।

- These amendments aim to control the unabated and unwarranted negative impact of online gaming activities on users, especially children and other vulnerable sections of society.
- \* The Rules disallow intermediaries to host or display any advertisement or surrogate advertisement or promotion of an online game that is not a permissible online game.
- \* The Rules will ensure that online games or sites that involve wagering will be banned completely, including advertising or any time of presence. For this, the Rules introduce the concept of a 'permissible online game'.

#### EY FORECAST FOR 2025

- ◆ The online gaming segment is expected to grow at a CAGR of 20% over four years to reach INR 231 billion by 2025.
- ◆ Transaction-based gaming is estimated to grow at a CAGR of 21% to reach INR 183 billion and contribute 79% of total segment revenues..

#### COMMENT

- ◆ Indian regulations have never kept pace with fastmoving events. There is no coherent regulatory policy to guide online gaming.
- ◆ Piecemeal steps have been taken recently to amend the IT Rules 2021 to bring in regulations, mainly to regulate and even ban wagering on online gaming.
- ◆ A new tax regime is in place whereby TDS will be deducted at 30% of net winnings from any online platform.
- ◆ *Argus Partners* pithily states:
  - In effect, the Government has banned any online real money game that involves wagering on any outcome.
  - However, the Amendment fails to define 'wagering precisely'.
  - Further, it appears that if an online real money game involves any wagering, it shall not be eligible to be verified as a permissible game, even if the game is predominantly a game of skill.
  - This approach would be contrary to the verdict given by courts wherein they have distinguished

- इन संशोधनों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर **ऑनलाइन गेमिंग** गितिविधियों के वेरोकटोक और अनुचित नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करना है।
- नियम विचौलियों को किसी भी विज्ञापन की मेजबानी या प्रदर्शन करने या सरोगेट विज्ञापन या किसी ऐसे ऑनलाइन गेम के प्रचार की अनुमित नहीं देते हैं जो एक अनुमेय ऑनलाइन गेम नहीं है।
- नियम यह सुनिश्चित करेगा कि ऑनलाइन गेम या साइटें जिनमें सदटेबाजी शामिल है, उन्हें विज्ञापन या उपस्थिति के किसी भी समय सहित पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। इसके लिए नियम एक 'अनुमेय ऑनलाइन गेम' की अवधारणा पेश करते हैं।

#### 2025 के लिए ईवाई पूर्वानुमान

- ◆ उम्मीद है कि ऑन लाइन गेमिंग सेगमेंट चार वर्षों में 20% सीएजीआर से बढ़कर 2025 तक 231 बिलियन रूपये तक पहुंच जायेगा।
- अनुमान है कि लेन-देन आधारित गेमिंग 21% की सीएजीआर से बढ़कर 183 बिलियन रूपये तक पहुंच जायेगी और कुल सेगमेंट राजस्व में 79% का योगदान करेंगी।

#### टिप्पणी

- भारतीय नियम कभी भी तेजी से आगे बढ़ने वाली घटनाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पाये हैं।ऑनलाइन गेमिंग को निर्देशित करने के लिए कोई सुसंगत नियामक नीति नहीं हैं।
- आईटी नियम 2021 में संशोधन करने के लिए हाल ही में टुकड़े— टुकड़े कदम उठाये गये हैं, तािक मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग पर सदटेबाजी को विनियमित और प्रतिवंधित किया जा सके।
- एक नयी कर व्यवस्था लागू हो गयी है जिसके तहत किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुद्ध जीत पर 30% टीडीएस काटा जायेगा।
- ◆ **आर्गस पार्टनर्स** ने सारगर्भित रूप से **कहा है**ः
  - वास्तव में सरकार ने किसी भी ऑनलाइन वास्तविक पैसे के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें किसी भी परिणाम पर दांव लगाना शामिल है।
  - हालांकि संशोधन 'सटीक रूप से दांव लगाने को परिभाषित करने में विफल रहता है।
  - इसके अलावा ऐसा प्रतित होता है कि यदि किसी ऑनलाइन रियल मनी गेम में कीं दांव लगाना शामिल है, तो यह एक अनुमत गेम के रूप में सत्यापित होने के योग्य नहीं होगा, भले ही गेम मुख्य रूप से कौशल का गेम हो।
  - यह दृष्टिकोण अदालतों द्वारा दिये गये फैसले के विपरीत

between games of skill and games of chance and have held any prohibition on the former to be ultra vires the Constitution. "

- This writer fervently hopes that a compendium of new laws to regulate and enable the burgeoning Digital Economy will be passed by Parliament, hopefully by the winter session.
- Till then, hopefully, Government and Regulators will continue to enable the healthy growth of all media industries without using a heavy hand as has become the norm recently.

#### WILL SEBI INVESTIGATIONS SCUTTLE THE ZEE SONY **MERGER?**

- The merger of **Zee** and **Sony** was agreed to in **April 2021**. The objective was to bring into being a **10** 
  - billion dollar media behemoth to take on the large US-based entities like Disney Star/ Amazon Prime and Google.
- As part of the deal, Zee founder Mr Subhash Chandra's son, Mr Punit Goenka, would continue to be the combined company's Managing Director and CEO.
- In addition, Sonv would pay a **non-compete** fee to promoters of Zee, which they would use to infuse
  - primary equity capital into SPN, allowing them to buy shares of the company.
- In **July 2022**, **Zee** received approval for the merger from the two stock exchanges.

#### SEBI INVESTIGATIONS CAUSE NEW **ROADBLOCKS**

In May 2023, during a key hearing to process the merger, lawyers for the two stock exchanges informed the NCLT of an interim order passed on April 25 2023, against Shirpur Gold Refinery an Essel Goenka company, accusing it of devising "a होगा जिसमें उन्होंने कौशल के खेल और मौका के खेल के बीच अंतर किया है और पूर्व पर किसी भी प्रतिबंध को संविधान के दायरे से बाहर माना है।

- इस लेखक को पूरी उम्मीद है कि बढ़ती **डिजिटल अर्थव्यवस्था** को विनियमित करने और सक्षम करने के लिए नये कानुनों का एक संग्रह संसद द्वारा पारित किया जायेगा, उम्मीद है कि यह शीतकालीन सत्र तक हो जायेगा।
- तब तक उम्मीद है कि सरकार और नियामक बिना किसी सख्ती के सभी मीडिया उद्योगों के स्वस्थ विकास को सक्षम बनाना जारी रखेंगे, जो कि हाल में देखने सुनने में आया है।

## सी. क्या सेबी की जांच जी सोनी विलय को विफल कर देगी?

◆ जी और सोनी के विलय पर अप्रैल 2021 में सहमित हुई थी। इसका उद्देश्य डिज्नी स्टार/अमेजन प्राइम और गूगल जैसी बडी अमेरिका स्थित संस्थाओं को टक्कर देने के लिए 10 विलियन डॉलर की मीडिया दिग्गज कंपनी बनाना था।

- सौदे के हिस्से के रूप में जी के संस्थापक श्री सुभाष चंद्रा के बेटे श्री पुनीत गोयनका, संयुक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक
  - और **सीईओ** बने रहेंगे।
  - इसके अलावा. सोनी. जी के प्रमोटरों को एक गैर-प्रतिस्पर्धा शल्क का भगतान करेगी, जिसका उपयोग वे एसपीएन में प्राथमिक इक्विटी पंजी डालने के लिए करेंगे, जिससे उन्हें कंपनी के शेयर खरीदने की अनुमति मिलेगी ।
- जुलाई 2022 में, जी को दो स्टॉक एक्सचेंजों से विलय के लिए मंजुरी मिल गयी।

### सेबी की जांच से नयी बाधायें पैदा होती है

 मई 2023 में, विलय की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान दो स्टॉक एक्सचेंजों के वकीलों ने एनसीएलटी को 25 अप्रैल 2023 को ऐसल गोयनका कंपनी शिरपर गोल्ड रिफाइनरी के खिलाफ पारित एक अंतरिम आदेश की जानकारी दी, जिसमें उस पर '**आईबीसी** प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए शिरपुर से धन स्थानांतरित करने और अपने खातों में स्थानांतरित



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange Board of India

- well-designed scheme devised by the Promoters to move the funds out of **Shirpur** and transfer to their accounts while misusing the **IBC** process".
- ◆ The NCLT directed the Stock Exchange lawyers to check with SEBI whether the approval for the merger granted by the stock exchanges in July 2022 stood and whether the payment of non-compete fees in Mauritius was in accordance with SEBI Regulations.
- ◆ Zee filed an appeal to the National Companies Appellate Tribunal, which set aside the NCLT Order, stating that natural justice opportunity be given to Zee to voice its objections to both directions of NCLT.
- ◆ Zee received another setback by an interim order dated 12/06/2023 directing that the Chairman Emeritus, Mr Subhash Chandra, and his son Mr Punit Goenka step down from the Board of Zee and cease to be Key Management Personnel due to alleged diversion of Rs. 200 crores to seven group concerns without knowledge of the Board.
- ◆ Mr Subhash Chandra and Mr Punit Goenka filed appeals in SAT. The SAT heard arguments at length and reserved judgment. Based on the contentious arguments made, the case can go either way.

#### **COUNTER AFFI DAVIT BY SEBI**

- ◆ SEBI filed an extraordinarily strong counteraffidavit to SAT justifying its interim order. It revealed that the fresh investigation arose from the settlement petition filed by Shirpur Refineries, an Essel Goenka group company.
- ◆ SEBI stated in the affidavit that Shirpur's case reflects a contrived scheme with a set of sham transactions meant to mislead and facilitate a circuitous movement of funds.
- ◆ SEBI initiated the process of obtaining bank statements from the various banks involved and tracing the source of money used by the related party to 'repay' ZEEL.
- ◆ Upon investigating the transactions, **SEBI** found some glaring irregularities.
- ◆ "While **ZEEL** claimed to have received repayment

- करने के लिए प्रमोटरों द्वारा तैयार की गयी एक 'अच्छी तरह से डिजाइन की गयी योजना तैयार करने का आरोप लगाया गया था।
- एनसीएलटी ने स्टॉक एक्सचेंज के वकीलों को सेबी से जांच करने का निर्देश दिया कि क्या जुलाई 2022 में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दी गयी विलय की मंजूरी कायम है और क्या मॉरीशस में गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क का भुगतान सेबी नियमों के अनुसार है।
  - ◆ जी ने राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की, जिसने एनसीएलटी के आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि एनसीएलटी के दानों निर्दे शों पर अपनी आपित्तयां व्यक्त करने के लिए जी को प्राकृतिक न्याय का अवसर दिया जाना चाहिए।
  - ♦ जी को 12/06/2023 के अंतरिम आदेश से एक और झटका लगा, जिसमें निर्देश दिया गया कि चेयरमेन एमेरिटस, श्री सुभाष चंद्रा और उनके बेटे श्री पुनीत गोयनका, जी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बोर्ड की जानकारी के बिना सात समूहों संस्थाओं को 200 करोड़ों रूपये के कथित हेरफेर के कारण मुख्य प्रबंधन कार्मिक से भी हटा दिया गया।
- ♦ श्री सुभाष चंद्रा और श्री पुनीत गोयनका ने एसएटी पर अपील दायर की।सैट ने विस्तार से दलीलें सुनी और फैसल सुरक्षित रख लिया।दिये गये विवादास्पद तर्कों के आधार पर मामला किसी तरफ भी जा सकता है।

#### सेबी द्वारा जवाबी हलफनामा

- सेबी ने अपने अंतिरम आदेश को उचित ठहराते हुए एसएटी को एक असाधारण मजबूत जवाबी हलफनामा दायर किया। इससे पता चलता है कि ताजा जांच एसेल गोयनका समूह की कंपनी शिरपुर रिफाइनरीज द्वारा दायर निपटान याचिका से सामने आयी है।
- सेबी ने हलफनामे में कहा है कि शिरपुर का मामल फर्जी लेनदेन के सेट के साथ एक काल्पनिक योजना को दर्शाता है जिसका उद्देश्य गुमराह करना और धन के एक घुमावदार लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है।
- सेवी ने इसमें शामिल विभिन्न बैंकों से बैंक विवरण प्राप्त करने और संबंधित पक्षों द्वारा जेडईईएल को 'चुकाने के लिए उपयोग किये गये धन के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की।
- लेनदेन की जांच करने पर, सेबी को कुछ गंभीर अनियमितताएं मिलीं।
- जबिक जेडईईएल ने यस बैंक द्वारा समायोजना के कारण संबंधित

33 SATELLITE & CABLE TV JULY 2023

NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण

- of money from the related parties on account of the adjustment by Yes Bank, SEBI found that such money originated from ZEEL itself and group companies of the Essel Group (which includes ZEEL). Therefore, effectively, ZEEL funded its repayment," the Regulator said.
- ◆ In the instant case, we have a situation before us where the Chairman Emeritus and the Managing Director and CEO of this large-listed company are involved in a myriad of different schemes and transactions through which vast amounts of public money belonging to listed companies are diverted to private entities owned and controlled by these persons.

#### COMMENT

- ◆ On June 22 2023, Mr Punit Goenka held a series of media briefings to state that the merger with Sony would go ahead irrespective of whether he continued as CEO/MD of Zee.
- ◆ He told the **Economic Times**, "The **Zee Sony** merger holds immense significance regardless of my position as CEO. The resulting entity will be in **Sony's** control, and they have chosen to retain me as promoter, MD, and CEO.
- ◆ He further claimed that, however, if the law prevents me from holding these positions, should the merger be allowed to fail? Such an outcome would negatively impact everyone involved in the ecosystem and the sector as a whole."
- ◆ Of course, Mr Punit Goenka is advised by a big team of experienced lawyers and consultants. Even so, corporate propriety demanded that when NCLAT refused to grant an interim stay, Mr Goenka should have stepped down from the Board till the litigation in courts/ SEBI investigation was over or at least proceeded on leave.
- ◆ Listed Companies have experienced Boards consisting of independent directors and non-executive internal directors. The Board automatically steps up and gives guidance in such situations. Evidence of this is lacking at the present stage.
- ◆ Regardless of Mr Punit Goenka's continuation as MD/CEO, this writer expects the merger process to be completed by March 2024. ■

- पक्षों से पैसे का पुनर्भुगतान प्राप्त करने का दावा किया है, सेवी ने पाया कि ऐसा पैसा जेडईईएल और एसेल समूह की समूह कंपनियों (जिसमें जेडईईएल भी शामिल है) से आया है। इसलिए, प्रभावी रूप से, जेडईईएल ने इसके पुनर्भुगतान के लिए धन दिया. नियामक ने कहा।
- ♣ मौजूदा मामले में, हमारे सामने एक ऐसी स्थिति हैं जहां इस बड़ी-सूचीबद्ध कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस और प्रबंध निदेशक और सीईओ असंख्य विभिन्न योजनाओं और लेनदेन में शामिल हैं जिनके माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित सार्वजनिक धन की बड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। इन व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली निजी संस्थाओं की ओर मोड दिया गया।

#### टिप्पणी

- 22 जून 2023 को श्री पुनीत गोयनका ने मीडिया ब्रीफिंग की एक श्रृंखला आयोजित की जिसमें कहा गया है कि सोनी के साथ विलय आगे बढ़ेगा भले ही वह जी के सीईओ/एमडी के रूप में बने रहें।
- उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि 'सीईओ के रूप में मेरी स्थिति की परवाह किये बिना, जी-सोनी का विलय बहुत महत्व रखता है। परिणामी इकाई सोनी के नियंत्रण में होगी और उन्होंने मुझे प्रमोटर, एमडी और सीईओ के रूप में बनाये रखने के लिए चुना है।'
- उन्होंने आगे दावा किया है कि हालांकि, अगर कानून मुझे इन पदों पर रहने से रोकता है, तो क्या विलय को विफल होने दिया जाना चाहिए?इस तरह के परिणाम से पारिस्थितिकी तंत्र और पूरे क्षेत्र में शामिल सभी लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा'।
- वेशक, श्री पुनीत गोयनका को अनुभवी वकीलों और सलाहकारों की एक बड़ी टीम सलाह देती है। फिर भी, कॉपीरेट औचित्य की मांग है कि जब एनसीएलटी ने अंतरिम रोक देने से इंकार कर दिया, तो श्री गोयनका को अदालतों में मुकदमेवाजी /सेवी जांच समाप्त होने तक बोर्ड से हट जाना चाहिए था या कम से कम छुदटी पर चले जाना चाहिए था।
- सूचीबद्ध, कंपनियों के पास अनुभवी बोर्ड हैं जिनमें स्वतंत्र निदेशक और गैर-कार्यकारी आंतरिक निदेशक शामिल हैं। ऐसी स्थिति में बोर्ड स्वतः ही आगे आता है और मार्गदर्शन देता है। वर्तमान स्तर पर इसके साक्ष्य का अभाव है।
- श्री पुनीत गोयनका के एमडी/सीईओ बने रहने के बावजूद इस लेखक को उम्मीद है कि विलय प्रक्रिया मार्च 2024 तक पूरी हो जायेगी।